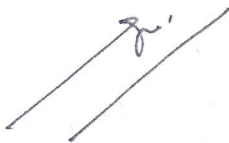


**Commissioner State Tax Uttarakhand**  
(State Tax Department)  
No : ~~3258~~ /CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18  
Dehradun :: Dated :: 04 October, 2017


**Notification**

In exercise of the powers conferred by section 54 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, and sub-rule (5) of rule 96A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, I, the Commissioner, hereby specifies conditions and safeguards for furnishing a Letter of Undertaking in place of a Bond by a registered person who intends to supply goods or services for export without payment of integrated tax -

- (i) all registered persons who intend to supply goods or services for export without payment of integrated tax shall be eligible to furnish a Letter of Undertaking in place of a bond except those who have been prosecuted for any offence under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) or any of the existing laws in force in a case where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees;
- (ii) the Letter of Undertaking shall be furnished on the letterhead of the registered person, in duplicate, for a financial year in the annexure to FORM GST RFD – 11 referred to in sub-rule (1) of rule 96A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 and it shall be executed by the working partner, the Managing Director or the Company Secretary or the proprietor or by a person duly authorised by such working partner or Board of Directors of such company or proprietor;



- (iii) where the registered person fails to pay the tax due along with interest, as specified under sub-rule (1) of rule 96A of Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, within the period mentioned in clause (a) or clause (b) of the said sub-rule, the facility of export without payment of integrated tax will be deemed to have been withdrawn and if the amount mentioned in the said sub-rule is paid, the facility of export without payment of integrated tax shall be restored.
2. The provisions of this notification shall *mutatis mutandis* apply in respect of zero-rated supply of goods or services or both made by a registered person (including a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit) to a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit without payment of integrated tax.

  
(Amit Singh Negi)  
Commissioner State Tax,  
Uttarakhand.

आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड

(राज्य कर विभाग)

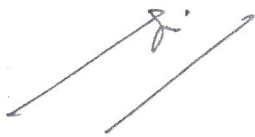
संख्या : 3258/आ0रा0क0उ0/जी0एस0टी0-विधि अनुभाग/2017-18

देहरादून :: दिनांक :: 04 अक्टूबर, 2017

### अधिसूचना

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 और उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, एतद्वारा, किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के लिए शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करता हूँ —

- (i) ऐसे मामले में, जहां अपवंचित कर की रकम दौ सौ पचास लाख रुपए से अधिक है, तथा जिन्हें उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) या किसी प्रवृत्त विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है, उन व्यक्तियों के सिवाय, ऐसे सभी व्यक्ति, जिनका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के पात्र होंगे;
- (ii) किसी वित्तीय वर्ष के लिए, परिवचन पत्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के शीर्षनामे पर, दो प्रतियों में, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 के उपाबंध में दिया जाएगा और यह कार्यरत भागीदार, प्रबंध निदेशक या कंपनी सचिव या स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे कार्यरत भागीदार या ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड या स्वत्वधारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा;
- (iii) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट देय कर और ब्याज का भुगतान उक्त उपनियम के खंड (क) अथवा खंड (ख) में उल्लिखित अवधि में नहीं कर पाता है तो यह माना जाएगा कि बिना एकीकृत कर का भुगतान किये निर्यात करने की जो सुविधा दी गई है, वह



वापस ले ली गई है और यदि उक्त उपनियम में उल्लिखित राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो बिना एकीकृत कर का भुगतान किये निर्यात करने की जो सुविधा दी गई है, वह बहाल हो जाएगी।

2. इस अधिसूचना के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों, सहित किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई भी है) द्वारा किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना किए गए माल या सेवाओं या दोनों के जीरो रेटेड प्रदाय के संबंध में लागू होंगे।

  
(अमित सिंह नेगी)

आयुक्त राज्य कर,

उत्तराखण्ड।